

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2015
दिनांक 31.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

आंध्र प्रदेश में एसबीएम-जी

†2015. डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आंध्र प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से अब तक वर्ष-वार आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि कितनी है;
- (ख) राज्य में एसबीएम-जी के अंतर्गत निर्मित व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) की वर्ष-वार संख्या कितनी है;
- (ग) क्या सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को कवर किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों के दूर-दराज और आदिवासी गांवों में शौचालय की पहुँच की पुष्टि के लिए हाल ही में कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम रहे; और
- (ङ) सरकार द्वारा वन, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में, जहाँ शौचालय कवरेज अपर्याप्त है, एसबीएम-जी लाभों की पहुँच, जागरूकता और वितरण में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) वर्ष 2014-15 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:

करोड़ रुपये में

वर्ष	निधि आवंटन	जारी निधि	व्यय
2014-15	262.25	116.1	101.82
2015-16	336.74	234.17	302.03

2016-17	342.21	342.21	381.05
2017-18	1219.88	1219.88	1151.3
2018-19	1381.18	1381.11	509.88
2019-20	395.76	248.11	231.99
2020-21	393.47	212.27	437.03
2021-22	437.64	58.26	386.83
2022-23	676.79	147.03	274.13
2023-24	50.00	0	290.81
2024-25	270.16	75.51	156.28
कुल	5766.08	4034.65	4223.18

(ख) आन्ध्र प्रदेश में एसबीएम (जी) के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से अब तक निर्मित व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	वर्ष	निर्मित आईएचएचएल
1	2014-15	159931
2	2015-16	336453
3	2016-17	725583
4	2017-18	2142853
5	2018-19	517650
6	2019-20	252585
7	2020-21	84186
8	2021-22	4121
9	2022-23	2819
10	2023-24	119348
11	2024-25	8338
12	2025-26 (अब तक)	24082
कुल:		4377949

(ग) से (घ) आंध्र प्रदेश सरकार ने कार्यपरिपूर्णता आधार पर आईएचएचएल का निर्माण पूरा कर लिया है और राज्य को जुलाई 2018 में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश सरकार ने आदिवासी गांवों में शौचालय की सुविधा प्रदान करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में सामग्री के परिवहन के लिए प्रति आईएचएचएल 3000 रुपये (एसबीएम-जी दिशानिर्देशों के अनुसार 12,000 रुपये के साथ) की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मंजूर की है। स्वच्छ आंध्र निगम, आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में गांव और पारिवारिक दोनों स्तरों पर खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति का सर्वेक्षण कर रही है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) के कवरेज का मूल्यांकन करना,

कमियों की पहचान करना और ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने के लिए आवश्यक हस्तक्षेपों को लागू करना है। इसके अतिरिक्त, यह स्वच्छता कवरेज, अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता व्यवहारों के संबंध में ग्राम-स्तरीय सूचना प्रदान करेगा। अब तक, 80% सर्वेक्षण पूरा हो गया है और शेष 20% सर्वेक्षण प्रगति पर है। इस मूल्यांकन में आन्ध्र प्रदेश के दूरस्थ और जनजातीय गांवों सहित सभी गांव शामिल हैं।

(ड) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी गांवों और शैक्षिक संस्थाओं में एसबीएम(जी) कार्यकलापों के बारे में व्यापक जागरूकता का प्रसार करने के लिए सूचना, शिक्षा तथा संचार (आईईसी) संबंधी कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं। जिलों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे सभी पात्र लाभार्थियों से प्राथमिकता के आधार पर शौचालयों की आवश्यकता से संबंधित सूचना प्राप्त करें और शौचालय निर्माण को पूरा करने के लिए तत्काल आवश्यक स्वीकृति प्रदान करें। स्वीकृतियां दी जाती हैं तथा निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हर महीने के तीसरे शनिवार को स्वच्छ आंध्र दिवस के रूप में घोषित किया है और हर महीने स्वर्ण आंध्र - स्वच्छ आंध्र कार्यक्रम स्वच्छता गतिविधियों के बारे में अधिक जागरूकता का प्रसार करने, एसबीएम गतिविधियों में सार्वजनिक भागीदारी के लिए अलग-अलग विषयों के साथ आयोजित किया जा रहा है। सभी सरकारी अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों को भाग लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भी स्वर्ण आंध्र - स्वच्छ आंध्र कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।
